

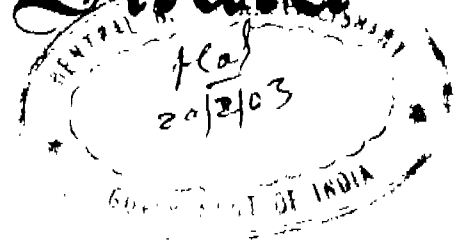


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 537]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2002/ज्येष्ठ 23, 1924

No. 537]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2002/JYAISTHA 23, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2002

का.आ. 632(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने जब तक उस सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो तब तक किसी परियोजना के किसी क्रियाकलाप के विस्तार या आधुनिकीकरण या आरंभ किए जाने के संबंध में कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित किए थे ;

और, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1)

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 2 के उप-पैरा 1 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि पाइपलाइन और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्रत्येक जिले में, जिनसे होकर पाइपलाइन या राजमार्ग गुजरते हैं, लोक सुनवाई की जाएगी । :

(ii) पैरा 3 के उप-पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) अनुसूची 1 की प्रविष्टि सं० 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 27 के अंतर्गत आने वाली कोई मद यदि नई परियोजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट 100 करोड़ रुपए से कम है और परियोजनाओं के विस्तारण/आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए से कम है ।”;

(iii) पैरा 3 के उपपैरा (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ङ) अनुसूची 1 की प्रविष्टि सं० 8 के अंतर्गत आने वाली कोई मद, यदि वह उत्पाद, अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1037(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1989 के अंतर्गत आता है ।

(च) सिंचाई सेक्टर में आधुनिकीकरण परियोजनाएं, यदि अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र 10, 000 हेक्टेयर से कम है या परियोजना लागत 100 करोड़ रुपए से कम है ।”;

(iv) अनुसूची 4 में पैरा (1) में, मद सं० (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(i) एक कार्यपालक सार, जिसमें परियोजना की मुख्य बातें अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (प.प्र.नि.) के साथ होगी । तथापि पाइपलाइन परियोजना के लिए, पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । किन्तु पर्यावरणीय प्रबंध, जिसके अंतर्गत जोखिम शमन, उपाय भी हैं, अपेक्षित हैं ।”

(ii) पैरा (4) में “कार्यपालक सार” शब्दों के स्थान पर “कार्यपालक सार और पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट” शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[सं. जेड-12013/4/89-1 अ. 1 (भाग)]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) दिनांक 27 जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई व बाद में सं. का.आ. 356(अ) दिनांक 4 मई, 1994, का.आ. 318(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1997, का.आ. 71(अ) दिनांक 27 जनवरी, 2000, का.आ. 1119(अ) दिनांक 13 दिसम्बर, 2000, का.आ. 737(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2001 व का.आ. 1148(अ) दिनांक 21 नवम्बर, 2001 द्वारा यथा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2002

S.O. 632(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 60(E), dated 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said Rules), the Central Government imposed certain restrictions and prohibition on the expansion or modernization of any activity or the undertaking of any project, unless environment clearance has been granted by the Central Government;

And Whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Rules provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And Whereas, the central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Act read with sub-rule (4) of rule 5 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:

In the said notification -

(i) In paragraph 2, in sub-para I, after clause (a), the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that for pipeline projects, Environmental Impact Assessment report will not be required:

Provided further, that for pipeline and highway projects, public hearing shall be conducted in each district through which the pipeline or highway passes through";

(ii) in paragraph 3, for sub para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(b) any item falling under entry no. 1,2,3,4,5,7,9,10,13,14,16,17,19,21,25,27 of Schedule-I if the investment is less than Rs 100 crores for new projects and less than Rs. 50 crores for expansion / modernization projects.";

(iii) in paragraph 3, for sub-para (e), the following sub-para shall be substituted, namely :-

"(e) any item falling under entry no. 8 of Schedule-I, if that product is covered by the notification G.S.R. 1037(E) dated 5th December, 1989.

(f) Modernization projects in irrigation sector if additional command area is less than 10,000 hectares or project cost is less than Rs. 100 crores.";

(iv) in Schedule IV, in paragraph (1), for item (i), the following item shall be substituted, namely :

"(i) An executive summary containing the salient features of the project both in English as well as the local language along with Environmental Impact Assessment (EIA). However, for pipeline project, Environmental Impact Assessment report will not be required. But Environmental Management Plan including risk mitigation measures is required."

(ii) in paragraph (4), for the words "Executive Summary", the words "Executive Summary and Environmental Impact Assessment report" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. Z-12013/4/89-IA. I(Part)]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Foot note - The Principal Notification was published vide number S. O. 60(E) dated the 27th January, 1994 and subsequently amended vide number S.O. 356 (E) dated the 4th May, 1994, S.O. 318 (E) dated the 10th April, 1997, S.O. 73(E) dated the 27th January, 2000, S.O. 1119 (E) dated the 13th December, 2000, S.O. 737(E) dated the 1st August, 2001 and S.O. 1148 (E) dated 21st November, 2001.